House. Does it apply to Ministers of the Government ? Are they not prisoners of bureaucracy? (*Interruptions*) I will give one example. I have got many examples. There is the Rs. 72,000 Project for quick maturing of mustard-seeds. They deliberately suppressed it for 9 months—and I am using very strong words—and they gave the money when I started bamboozling them. And then what was the pretext given ? It was that the first instalment was for Rs. 12,000, Calcutta University has not complied with the requirement which they wanted them to do. I said, you have given the money, 12,000 or so. Have they complied with the requirement ? No, Sir. Then how could you give the money ? Well, they were waiting to see if Jyotirmoy Bosu could get defeated so that they could get the money back. There is a very powerful oilseed lobby in this country,—powerful edible oil lobby in this country ; they are working with the ICAR. I am charging.

I fully support Prof. Ranga who said that the D.G. cannot sit in judgement on his own activities. He can't chair the Governing body and the Standing Finance Committee. There is a thing called 'Warrant of Precedence' and MPs. occupy a fairly high position and in governmental meetings their warrant of precedence should not be lost sight of Rao Saheb, I request you to kindly consider that they are your honourable colleagues and don't treat them shabbily. Sir, if I wanted to penetrate into ICAR through the back-door, I would not have wanted shifting of its H. Q. Rao Saheb, you made a contradictory statement. The subordinate directors of the Institute are subordinate to the D. G. for administrative as well as financial matters. They have no freedom and what Mr. Rao Birendra Singh has chosen to say is not correct. Sir, he talked about potatoe. If it is all that good, why should it be sold at Rs. 2·50 per kilo ? (*Interruptions*). Now Dal, Why should it be sold at Rs. 6·00 per kilo. The rice yield per acre has come down in Cuttack. Why did it go down ? Mr. R. V. Swaminathan is not very far from there. You kindly find out. Now, sugar cane. What is the decline per hectare yield ; kindly don't take the House for a vide. I am Charging you how the per hectare yield has come down in many agricultural items. The scientists job is there to increase the production. During 1956-61, per hectare yield of pulses was 495 Kg. and in 1974-79, it was 493 Kg. What are they taking about ? Telling tales. There are many things on which a debate of this size cannot cover. It is the biggest organisation and there are a lot of Complications and mismanagements. Rao Saheb I beseech you once again, don't take anybody from the Opposition, but take your own party-men into confidence and divide the yok and let them do fact finding and report to you so that you are able to do substantial good to the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That this House do recommend that an All party Parliamentary Committee be constituted to enquire thoroughly into the target and performance of the Indian Council of Agricultural Research and also ascertain as to why in the last 33 years there had been no plan for agricultural production matching our needs fully."

The Motion was negatived.

20.3 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

LOAD SHEDDING IN THE CAPITAL

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, हम दिल्ली की जिस जगह में रहते हैं, दिल्ली में भी साउथ ऐवेन्यू, नार्थ ऐवेन्यू जहां कि

[श्री रशीद मसूद]

मैम्बर पार्लियामैंट रहते हैं, हमें उस दिक्कत का अहसास नहीं हो सकता, जो दिल्ली में और जगहों पर रहने वाले लोगों को पिछले एक या सवा साल से है। जहां कि यह तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कभी बिजली जायेगी, वहां भी हमारा तजुर्बा यह है कि अगस्त से अब तक बराबर बिजली जाती रही है। और जगहों की हालत क्या है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अगस्त से लेकर अब तक शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जिस दिन डेसू के बारे में कोई शिकायत अखबार में न आई हो। किसी न किसी जगह का कहीं न कहीं जिक्र होता है चाहे इस के अन्दरूनी झगडों का ही जिक्र हो।

तीन महीनों में 812 दफे ब्रेक-डाउन हुआ है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो यह 8 ब्रेक-डाउन रोजाना के हिसाब से बैठते हैं। आप इस से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली जैसी जगह में गर्मी के मौसम में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी ?

यही नहीं, एक आक्सीजन बनाने वाली कम्पनी को एक महीने में 42 ब्रेक-डाउन का सामना करना पड़ा। आक्सीजन जिन्दगी के लिए जरूरी चीज है, इसके सलैन्डर्स अस्पतालों में सप्लाई होते हैं, वहां पर इतने ब्रेक-डाउन अगर होते हैं तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां की हुकूमत इन्सान की जिन्दगी को कुछ नहीं समझती है।

यह जो ब्रेक-डाउन होते रहे हैं, यह कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी काफी ब्रेक-डाउन हुए हैं और होते रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों में जो ब्रेक-डाउन देखने में आये है, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि बगैर किसी नोटिस के ब्रेक-डाउन हो जाते हैं। कभी कभी दो घंटे के नोटिस के बाद 6, 6, और 8, 8 घंटे तक बिजली गायब रहती है। जब अथोरीटीज से पूछा गया कि क्या वजह हैं, बिजली को बगैर नोटिस के क्यों गायब कर रहे हैं, तो जवाब मिलता रहा कि हैड क्वार्टर जो डेसू का हैं वह चीफ इंजीनियर के आफिस से 8 किलोमीटर दूर है। आप जानते हैं कि हमारे यहां के टेलीफोन इस कद्र उमदा काम करते हैं कि मिनिस्टर्स को भी किसी से बात करने के लिए बैठे रहना पड़ता है। ब्रेक-डाउन का नोटिस अखबारों को नहीं जा पाता है, जिस से लोगों को बहुत परेशानी होती है। डेसू के द्वारा कानून का उल्लंघन हुआ है। इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत चौबीस घंटे की सप्लाई में 2.5 परसेंट कुछ माइनस या प्लस—की रुकावट हो सकती है, लेकिन कई लोकेलिटीज में 50, 60 परसेंट—11 घंटे तक—ब्रेक-डाउन रहा है।

आज अखबारों में देखने को मिला कि बिजली के मामले में दिल्ली सैल्फ-सफिसेंट हो गई है, वह दूसरों को भी बिजली दे रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बिजली की रीसैटलमैंट कालोनीज को बिजली सप्लाई कर दी है, क्या उसने लोगों को दिए जाने वाले गलत बिलों के बारे में कोई एक्शन लिया है, क्या उसने बिजली की चोरी की तरफ ध्यान दिया है। मैं समझता हूं कि इन सारी खराबियों की कुछ वजुहात हैं, जिनको दूर किए बगैर हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है।

एक बात तो यह है कि इस वक्त कोई प्लानिंग नहीं है कि किस वक्त किस लोकेलिटी में बिजली का शट-डाउन होगा। हिन्दुस्तान टाइम्ज और इंडियन एक्सप्रैस वगैहरा अखबारों में यह बात

कही गई है कि शट-डाउन बगैर प्लानिंग के होता हैं । जब आफिसर्ज से पूछते हैं कि कितनी जगहों को कितने घंटे बिजली से महरूम रखा जायेगा, तो कोई जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि बगैर प्लानिंग के काम हो रहा है ।

हमारे यहां पावर जनीरेटिंग एथारिटी भी दो अलग अलग हैं, जिनका आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है । उनमें आपस में पूरी कोआर्डिनेशन हुए बिना ठीक सप्लाई नहीं रखी जा सकती है। इस लिए इस डिफेक्ट को दूर करना चाहिए ।

इंडियन एक्सप्रेस में कहा गया है कि इस गड़बड़ की सब से बड़ी वजह—मैं माफी चाहूंगा उस तरफ के लोगों से—पोलीटिकल इन्टरफीयरेंस है । अगर इस वजह से लोगों को दिक्कत और परेशानी हो, तो यह बहुत तक्लीफदेह बात हैं । 3 तारीख के **इंडियन एक्सप्रेस** में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस (आई) कमेटी के प्रैजिडैन्ट ने जा कर एथारिटीज को प्रेशराइज किया कि किसी पार्टीकुलर मामले में एक पार्टिकुलर फर्म से चीजें खरीदी जायें । जब एक आफिसर ने इन्कार किया, तो लैफ्टिनेन्ट-गवर्नर को शिकायत हुई । नतीजा यह हुआ कि उस आफिसर से एक्सप्लेशन काल किया गया । अखबार में यह भी कहा गया हैं कि मिनिस्टर साहब की तरफ से भी इन्टरफीयरेंस हुआ है । यह रोजाना की इन्टरफियरेंस खत्म होनी चाहिए ।

तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां के अफसरान और वर्कर्ज में रेपोर्ट नहीं है, उनका आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद नहीं हैं । उसकी वजह है फ्रस्ट्रेशन—डेसू के मुलाजिमीन फ्रस्ट्रेटिड है, क्योंकि एक एसिस्टैन्ट इंजीनियर को एक्सीक्यूटिव इंजीनियर बनने के लिए 18 साल लग जाते हैं, और उससे आगे प्रमोशन का सवाल ही नहीं है । इस लिए उनमें अपने काम के बारे में जो जोश होना चाहिए, वह देखने को नहीं मिलता हैं । प्रोमोशन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि अफसरों की दिलचस्पी बरकरार रहे ।

डेसू में करीब करीब 30 परसेंट मुलाजिमीन और अफसर बाहर से डेपुटेशन पर आये हुए हैं । अगर वहीं के टैक्नीकल लोगों को तरक्की देकर रखा जाये, तो वे ज्यादा दिलचस्पी और मेहनत से काम करके उस आर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचा सकते हैं । बनिस्बत इस के कि उस के अन्दर डेपूटेशन पर लोग दूसरी जगह से जायें जो नान-टैक्निकल हैं और वे वहां जाकर काम करें । . . . (**व्यवधान**) . . . . अच्छा बन्द करता हूं, अगर आपका हुकुम है । देखिये, ये बोलने भी नहीं देते ।

मैंने जो बात कही है ये डिफैक्टस हैं और य मैंने इस लिए नहीं बतलाये हैं कि कोई क्रिटिसिज्म है आप का, बल्कि डैमोक्रेसी में यह जरूरी है कि डिफैक्टस को आपकी नालिज में लाया जाय और और आपके लिए भी वह जरूरी हैं कि आप उस को एक्सैप्ट करके उसे दूर करें ।

[شری رشید مسعود (سہارنپور) :

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب ہم دلی کی جس جگہ میں رہتے ہیں دلی میں ہی ساؤتھ ایوینیو نارتھ ایوینیو جہاں کہ ممبر پارلیمینٹ رہتے ہیں ہمیں اس وقت وہ احساس نہیں ہو سکتا جو دلی میں اور جگہ پر

[شری رشید مسعود]

رہنے والے لوگوں کو پچھلے ایک یا سوا سال سے ہے - جہاں کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی بجلی جائے گی وہاں بھی ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اگست سے اب تک برابر بجلی جاتی رہی ہے - اور جگہوں کی حالت کیا ہے اسکا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اگست سے لے کر جب تک شاید ہی کوئی دن ایسا گیا ہو جس دن ڈیسو کے بارے میں کوئی شکایت اخبار میں نہ آئی ہو - کسی نہ کسی جگہ کا کہیں نہ کہیں ذکر ہوتا ہے چاہے اس کے اندرونی جھگڑوں کا ہی ذکر ہو -

تین مہینے میں ۸۱۲ دفعہ بریک ڈاون ہوا ہے - اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ ۸ بریک ڈاون روزانہ کے حساب سے بیٹھتے ہیں - آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلی جیسی جگہ میں گرمی کے موسم میں رہنے والے لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی -

بھی نہیں ایک آکسیجن بنانے والی کمپنی کو ایک مہینے میں ۴۲ بریک ڈاون کا سامنا کرنا پڑا - آکسیجن زندگی کے لئے ضروری چیز ہے اس کے سلنڈرس ہسپتالوں میں سپلائی ہوتے ہیں وہاں پر اتنے بریک ڈاون اگر ہوتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کی حکومت انسان کی زندگی کو کچھ نہیں سمجھتی ہے -

یہ جو بریک ڈاون ہوتے رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے - اس سے پہلے بھی کافی بریک ڈاون ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں - لیکن پچھلے دنوں میں جو بریک ڈاون دیکھنے میں آئے ہیں سب سے افسوس ناک بات یہ ہے کہ بغیر کسی نوٹس کے بریک ڈاون ہو جاتے ہیں - کبھی کبھی دو گھنٹے کے نوٹس کے بعد ۶-۶ اور ۸-۸ گھنٹے تک بجلی غائب رہتی ہے - جب آتھورٹیز سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے بجلی کو بغیر نوٹس کے کیوں غائب کر رہے ہیں تو جواب ملتا رہا کہ ہیڈ کواٹر جو ڈیسو کا ہے وہ چیف انجینیر کے آفس سے ۸ کلو میٹر دور ہے - آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے ٹیلیفون اس قدر عمدہ کام کرتے ہیں کہ منسٹریز کو بھی کسی سے بات کرنے کے لئے بیٹھے رہنا پڑتا ہے - بریک ڈاون کا نوٹس اخباروں کو نہیں جا پاتا ہے جس سے لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے - ڈیسو کے دوارا قانون کا الّنگھن ہوا ہے - انڈین الیکٹریسٹی ایکٹ کے تحت چوبیس گھنٹے کی سپلائی میں ۲۵ پرسینٹ کچھ مائنس یا پلس کی رکاوٹ ہو سکتی ہے- لیکن کئی لوکلیٹیز میں

نہیں ہے - میں آپس میں پوری کو آرڈینیشن ہوئے بنا ٹھیک سپلائی نہیں رکھی جا سکتی ہے - اس لئے اس ڈفیکٹ کو دور کرنا چاہئے -

انڈین ایکسپریس میں کہا گیا ہے کہ اس گڑبڑ کی سب سے بڑی وجہ- میں معافی چاہوں گا اس طرف کے لوگوں سے - پولیٹیکل انٹر فیرینس ہے - اگر اس وجہ سے لوگوں کو دقت اور پریشانی ہو تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے - ۳ تاریخ کو انڈین ایکسپریس میں کہا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کانگریس (آئی) کمیٹی کے پریزیڈینٹ نے جا کر آنہوریٹیز کو پرشرائز کیا کہ کسی پرٹیکولر معاملے میں ایک پرٹیکولر فرم سے چیزیں خریدی جائیں- جب ایک آفیسر نے انکار کیا تو لیفٹیننٹ گورنر کو شکایت ہوئی - نتیجہ یہ ہوا کہ اس آفیسر سے ایکسپلینیشن کال کیا گیا - اخبار میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ منسٹر صاحب کی طرف سے بھی انٹرفیرینس ہوا ہے - یہ روزانہ کی انٹر فیرینس ختم ہونی چاہئے -

تیسرن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے افسران اور ورکرز میں رپورٹ نہیں ہے ان کا آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے - اسکی وجہ ہے فریسٹیشن - ڈیسو کے ملازمین فریسٹیٹڈ ہیں ۵۰-۶۰ پرسینٹ ۱۱ گھنٹے تک بریک ڈاون رہا ہے -

آج اخباروں میں دیکھنے کو ملا کہ بجلی کے معاملے میں دلی سیلف سیفیشینٹ ہو گئی ہے وہ دوسروں کو بھی بجلی دے رہی ہے- لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سرکار نے دلی کی ری سٹلیمینٹ کالونیز کو بجلی سپلائی کر دی ہے کیا اس نے لوگوں کو دیئے جانے والے غلط بلوں کے بارے میں کوئی ایکشن لیا ہے کیا اسلئے بجلی کی چوری کی طرف دھیان دیا ہے - میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری خرابیوں کی کچھ وجوہات ہیں - جنکو دور کئے بغیر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے -

ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ کس وقت کس لوکلٹی میں بجلی کشت ڈاون ہوگا - ہندوستان ٹائمز اور انڈین ایکسپریس وغیرہ اخباروں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شت ڈاون بغیر پلاننگ کے ہوتا ہے - جب آفیسرز سے پوچھتے ہیں کہ کتنی جگہوں کو کتنے گھنٹے بجلی سے محروم رکھا جائیگا تو کوئی جواب نہیں ملتا ہے کیونکہ بغیر پلاننگ کے کام ہو رہا ہے-

ہمارے یہاں پاور جینریٹنگ آتھورٹی بھی دو الگ الگ ہیں جن کا آپس میں کوئی کوآرڈینیشن

[شری رشید مسعود]

کیونکہ ایک ایسسٹینٹ انجینئر کو ایکسکیوٹیو انجینیئر بننے کے لئے ۱۸ سال لگ جاتے ھیں اور اس سے آگے پروموشن کا سوال ھی نہیں ھے - اس لئے ان میں اپنے کام کے بارے میں جو جوش ھونا چاھئے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا ھے - پروموشن کا طریقہ ایسا ھونا چاھئے کہ افسروں کی دلچسپی برقرار رھے -

تیسرو میں قریب قریب ۳۰ پرسینٹ ملازمین اور افسر باھر سے ڈیپوٹیشن پر آئے ھوئے ھیں - اگر وھیں کے ٹیکنیکل لوگوں کو ترقی دے کر رکھا جائے تو وہ زیادہ دلچسپی اور محنت سے کام کرکے اس آرگنائزیشن کو فائدہ پہنچا سکتے ھیں - یہ نسبت اسکے کہ اسکے اندر ڈیپوٹیشن پر لوگ دوسری جگہ سے جائیں جو نون ٹیکنیکل ھیں اور وہ وھاں جا کر کام کریں - . . . (انٹرپریشن). . . اچھا بند کرتا ھوں اگر آپ کا حکم ھے دیکھئے یہ بولنے بھی نہیں دیتے -

میں نے جو بات کہی ھے یہ ڈیفیکٹس ھیں اور یہ میں نے اس لئے نہیں بتلائے ھیں کہ کوئی کریٹس ازم ھے آپکا بلکہ ڈیموکریسی میں یہ ضروری ھے کہ ڈیفیکٹ کو آپکی نالج میں لایا جائے اور آپکے لئے بھی یہ ضروری ھے - کہ آپکو ایکسپوزٹ کرکے اسے دور کریں -

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : माननीय सदस्य ने बड़े अच्छे विचार रखे हैं । उन में कुछ बातो के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं ?। जहां तक दिल्ली में पावर सिचुयेशन का ताल्लुक है आप को यह जानकर खुशी होगी कि दिल्ली की पावर पोजिशन दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है । इस साल के नवम्बर के महीने से पिछले साल के नवम्बर के महीने का मुकाबिला करें तो 22 प्रतिशत पावर दिल्ली में ज्यादा हुई । सारे हिन्दुस्तान में 20 प्रतिशत ज्यादा हुई । तो दिल्ली सें हिन्दुस्तान के एवरेज से 12 प्रतिशत पावर ज्यादा जनरेट हुई नवम्बर के महीने में ।

लोड शेडिंग का जहां तक ताल्लुक है आप को सुन कर खुशी होगी कि लोड शेडिंग नवम्बर के महीने में बडी मामूली सी हुई । पिछले साल नवम्बर के महीने में 18 दिन लोड शेडिंग हुई और इस साल सिर्फ दो दिन हुई । दिस्सम्बर के महीने में पिछले साल 3 दिन हुई और इस साल एक दिन हुई । दूसरे दिन इस लिए किया कि प्रधान मंत्री का एक पालिसी डेसीशन है कि हमें ऐग्रीकल्चरिस्ट्स को पावर देनी है ।

राजस्थान से रिक्वैस्ट आई कि वहां के एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिए पावर चाहिए तो प्रधान मंत्री ने कहा कि दिल्ली में लोड-शेडिंग कीजिए और राजस्थान में पावर दीजिए । इस लिए यह करना पड़ा । सिर्फ फार्मर्स के लिए यह डेसीशन लेना पड़ा । हम फार्मर्स के लिए दिल्ली में पावर दे रहे हैं । यू० पी० के फार्मर्स के लिए अक्टूबर में 11.3 मिलियन यूनिट्स पावर हमने दी, नवम्बर में 29.3 मिलियन यूनिट्स पावर उन को दी । दिसम्बर में 15 तारीख तक यू० पी० के फार्मर्स के लिए हम ने 7.7 मिलियन

यूनिट्स पावर दी । इसी तरह से राजस्थान को अक्टूबर में 10.6 मिलियन यूनिट्स पावर दी और 6.2 मिलियन यूनिट्स पावर 15 तारीख दिसम्बर तक दी । इसी ढंग से हमने जम्मू और काश्मीर को दी, बी एम बी को दी जो पंजाब के फार्मर्स की पावर देते हैं । इस तरह से बाहरी स्टेट्स को भी पावर हम दे रहे हैं, इतनी अच्छी पोजीशन दिल्ली में पावर की हो रही है । तो जहां तक पावर का क्वेश्चन है दिल्ली में एडीकेट पावर हैं और नये नये पावर स्टेशन, नये नये यूनिट लग रहे हैं जिस से पावर की पोजीशन दिन पर दिन इम्प्रूव करती जायेगी । हमारे सेन्ट्रल पावर स्टेशन और दूसरी जगहों में भी लग रहे हैं जहां से भी पावर हम को मिलेगी । ट्रांसमिशन लाइन्स काफी इम्प्रूव कर रहे हैं।

जहां तक कालोनीज़ का ताल्लुक है पिछले साल सिर्फ पांच रिसेटिलमैन्ट कालोनीज़ को पावर दी गई । इस साल हमने 14 रिसेटिलमैन्ट कालोनीज़ को पावर दे दी है । सिर्फ एक कालोनी रह गई है, उस को भी जल्दी से जल्दी पावर दे देंगे । जो भी रिसेटिलमैन्ट कालोनीज़ है उन को हम जल्दी से जल्दी पावर पूरा कर देंगे । सिर्फ एक कालोनी रह गई है—ज्वालापुरी ।

जहां तक नये कनेक्शंस का ताल्लुक है पिछले साल साढ़े चार हजार कनेक्शन दिए जाते थे, इस साल सात हजार कनेक्शन हर महीने हम दे रहे हैं और हम लोगों ने एक क्रैश प्रोग्राम चलाया है जिस से जहां तक गरीब तबके का सवाल है ...(व्यवधान)... दिल्ली में वह हम दे रहे हैं, पावर भी दे रहे हैं और साथ साथ कनेक्शन भी दे रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं । जो अप्लीकेशंस पेंडिंग हैं उस में नार्मल पेडेंसी तो रहती ही है । उस में ऐसी कोई नई बात नहीं है ।

हम ने एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है जहां पर की टेकनिशियंस को ट्रेनिंग मिलती है, रिफ्रेशर कोर्स मिलता है । इसी तरह से पोल्यूशन को कम करने का प्रोग्राम शुरू किया है । इस ढंग से दिल्ली को जो पावर सप्लाई पोजीशन है वह इम्प्रूव करते जा रहे हैं ।

आप ने कुछ बातें और कहीं । जहां तक ताल्लुक है मिनिस्टर का, इंडियन एक्सप्रेस प्रेस में दूसरे तीसरे दिन खबर आ गई थी कि वह खबर गलत है । मिनिस्टर के बारे में तो उन्होंने फ्रन्ट पेज पर छापा लेकिन जो उसका कांट्रेडिक्शन था उसको दूसरे तीसरे पेज पर कर दिया । इसलिए आप ने उसे नहीं पढ़ा वरना यह कांट्रेडिक्शन इंडियन एक्सप्रेस ने ही कर दिया था ।

तो इसके बारे में जहां तक डेसू और बदरपुर का सवाल हैं, हमारी सी ए एक आर्गेनाइज़ेशन है सेंटर की जो दोनों को कोआर्डिनेट करती है, बदरपुर और डेसू को और इस समय दोनों का अच्छा कोआर्डिनेशन है । अगर एक पावर स्टेशन की एक यूनिट को हम प्लान्ट मेंटिनेन्स में रखते हैं तो दूसरे पावर स्टेशन में तब तक शट डाउन नहीं करते जब तक कि पहले की यूनिट ठीक नहीं हो जाती । दोनों पावर स्टेशन्स के चीफ इंजीनियर्स रोज़ टेलीफोन पर बात करते हैं ताकि उनके दोनों के प्रोग्राम का पता रहे । इस ढंग से हर जगह इम्प्रूवमैंट की कोशिश की जा रही हैं और दिल्ली की पोज़ीशन जो है वह बाकी स्टेट्स से बहुत अच्छी है और जैसे जैसे वक्त आयेगा वैसे वैसे और इम्प्रूवमैंट होता जायेगा ।

जहां तक डैपुटेशन का सवाल हैं, टैक्निकल साइड में तो मुश्किल से शायद

[श्री विक्रम महाजन]

ही कोई डेपुटेशनिस्ट हो। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव और एकाउन्ट साइड का सवाल है वहां भी शायद एक परसेंट के करीब हो इसलिए 30 परसेंट की बात जो आपने कही है उसमें और इस फीगर में बहुत काफी फर्क है ।

प्रमोशन का जहां तक ताल्लुक है, हमने एक कमेटी बिठा दी है डिप्टी जनरल मैनेजर की चेयरमैनशिप में और उसमें सीनियर आफिसर्स रिकग्नाइज्ड यूनियन्स के हैं । बाद में हम देखेंगे इस सवाल को ।

जहां तक लेबर आफिसर्स और उनकी एसोसिएशन का सवाल है, उनकी जितनी प्राब्लम्स हैं उनको हम डेब ध्यान से देख रहे हैं, कमेटीज बैठा दी हैं जो कि उनकी प्राब्लम्स को देखें और अपनी रेकमेंडेशन्स दें फिर उसके बाद उन सवालों पर हम नजर डालेंगे । कोई उनके पास स्पेसिफिक इंस्टान्सेज हों तो वे दे सकते है । जब भी हम पावर शट डाउन करते हैं और प्लांट मेंटिनेंस होती हैं तो हर एरिया में सारी ट्रांसमीशन लाइन को चैक करना पड़ना है ....

श्री रशीद मसूद : मैं आपको पुराना बता सकता हूं , नया नहीं ।

[شری رشید مسعود : میں آپ کو پرانا بتا سکتا ہوں ، نیا نہیں ۔]

श्री विक्रम महाजन : आप अक्टूबर, नवम्बर या दिसम्बर का बताइये । वैसे इम्प्रूवमैन्ट करने में 4–5 महीने लगते है । जनवरी में सरकार आई थी, चार पांच महीन प्लान बनाने में लगे और अब उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं । अक्टूबर नवम्बर से इम्प्रूवमैन्टस होते चले आ रहे हैं । जब भी किसी एरिया में शट डाउन करते हैं प्लान्ट मैन्टिनेंस के लिए तो वहां तारों को देखना पड़ता है, ट्रांसमिशन लाइन को देखना पड़ता है और अखबारों में खबर दे दी जाती है कि फलां 2 एरिया में बिजली नहीं रहेगी । यह तो नार्मल प्रोसीजर है जिसको करना ही पड़ता है । यह हो सकता है कि किसी एरिया में कोई तार फ्यूज हो जाये या ट्रांसफार्मर फेल हो जाए लेकिन हमने एक नया मोनिटरिंग सेल बना दिया है डैसू में जो रोज इस बात की मोनिटरिंग करता है कि कौन से इलाके में बिना प्लांट मेंटिनेंस के, जिसके लिए कोई एनाउन्समैन्ट नहीं किया गया, बिजली फ्यूज हो गई और रोज उसकी रिपोर्ट मेरे पास आती है । इस तरह से हम इस बात पर चेक करते हैं और मुझे खुशी हैं कि जो नया तरीका हमने अपनाया है उससे दिल्ली की पावर पोजीशन इम्प्रूव कर गई है । इस के साथ साथ जहां तक वर्कर्स और आफिसर्स के कोआपरेशन की बात है, मैं उसकी बड़ी सराहना करता हूं ।

मैं एक बार फिर माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जहा पर इस प्रश्न को उठाकर उन्होंने दिल्ली की बड़ी सेवा की है और साथ ही हमें भी बहुत सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने का मौका दिया है ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समय काफी हो गया हैं इस लिए मैं सिर्फ प्रश्न ही करूंगा ।

पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पावर जेनरेशन में कमी आई है या नहीं ? क्या यह बात सही नहीं है कि पावर जेनरेशन में 65 परसेंट से लेकर 46 परसेन्ट तक कमी आई है ? आपने सारी चीजें बतलाई लेकिन यह नहीं बतलाया कि दिल्ली में बिजली की कितनी मांग है और आप कितनी पूर्ति करते हैं? मांग और आपूर्ति का कोई लेखा-जोखा आपने तैयार किया हैं या नहीं ? क्या आपने यह पता लगाया है कि एक साल में कितना पैसा रेवेन्यु के

माध्यम से आपके पास आता है ? उस अनुपात में कितनी बिजली आपने सप्लाई की और कितना इलैक्ट्रिक जनरेशन हुआ है ? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि आपने यह नहीं बतलाया है कि बिजली से लीकेज या पिलफ्रेज, समाचार पत्रों के मुताबिक जो है, वह है 4.5 लाख किलोवाट-पर-आवर । इसमें एक बार श्री के० सी० पंत के जमाने में छापा मारा गया था, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी इस तरह की छापा-मारी वगैरहा की है ? हमारे साथी ने बतलाया, प्राप्त जानकारी के अनुसार, 50 हजार से अधिक अनधिकृत कनैकशन्स हैं, इस सम्बन्ध में आपको कोई जानकारी है या नहीं है ? जून 1980 से शायद आपके यहां डेसू में जनरल मैनेजर की पोस्ट नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि उसके स्थान पर कौन काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं ? अंतिम बात, जो राजाध्यक्ष कमैटी नियुक्त की गई थी, उस कमैटी ने अपनी रिपोर्ट आपके पास दी है । उस कमेटी की क्या सिफारिशें हैं और कौन-कौन सी सिफारिशों को आप मानने जा रहे हैं ?

श्री विक्रम महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पावर जनरेशन का ताल्लुक है, आपको यह बात सुनकर खुशी होगी कि इस साल के पहले आठ महीने और पिछले साल 1979–80 के आठ महीने में क्रमशः 2,383 और 2,133 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई थी । इसलिए बिजली की बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई है ।

एक माननीय सदस्य : थर्मल पावर को ?

श्री विक्रम महाजन : दिल्ली में थर्मल पावर ही है, दिल्ली में हाइड्रो नहीं है, तो पिछले साल की अपेक्षा अधिक बिजली पैदा हुई है । यह आप का पहला प्रश्न हुआ ।

दूसरा प्रश्न, जहां तक रेड्स का ताल्लुक है, इस साल हमने 2,600 रेड्स किए है । जहां तक चोरी हुई है, जहां पिलफरेज हुआ है, होता रहा है, वहां पर इतने रेड्स किए हैं । आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमने इस बातों के लिए कितनी मेहनत की है ।

जहां तक रेवेन्यू की बात का ताल्लुक है, 1980–81 में 102 करोड़ रु० रेवेन्यू होने जा रहा हैं और यह काफी बढ़ोतरी है । इन्टरेस्ट के लिए हमने 80 लाख रु० रख दिया है, एडिशनल सिंकिंग फण्ड के लिए 10 लाख रु० रख दिया है, कोल इंडिया को 81 लाख रु० डैप्रिसिएशन में भी रुपया रख दिया है । इसलिए जो हमारी इनकम है, रेवेन्यू है, वह अच्छी पोजीशन में है ।

श्री राम विलास पासवान : जो इलैक्ट्रिक सप्लाई है, उसके बदले में कितना हुआ है ?

श्री विक्रम महाजन : मैं आपको इलैक्ट्रिक सप्लाई के बारे में ही बता रहा हूं, डेसू से 102 करोड़ रुपया आ रहा है । वह इलैक्ट्रिक सप्लाई का कोई काम नहीं करता है, वह सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है । हर साल जो हमारी रेवेन्यू की ग्रोथ है, वह 10 परसेंट रही है। यह भी इम्प्रूव कर गया है । जहां तक राजाध्यक्ष कमेटी की रिपोर्ट का ताल्लुक है, इस में काफ़ी रिकमेण्डेशनन्ज़ की गई हैं। उनकी रिपोर्ट को हम ने सदन की टेबिल पर रख दिया है । अगर अब मैं उन रिकमेण्डेशन्ज़ के बारे में कहना शुरू करूं तो एक घन्टा लग जायगा । इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो रिकमेण्डेशन्ज़ की हैं उनको हम एक्ज़ामिन कर रहे हैं । उनकी ज्यादा रिकमेण्डेशन्ज– स्टेट्स से ताल्लुक रखती हैं, इसके लिए हमें पावर मिनिस्टर्ज की कान्फ्रेंन्स बुला कर बातचीत करनी पड़ेगी। जब तक वे

[श्री विक्रम महाजन]

सहयोग नहीं देंगे तब तक ये सिफारिशें इम्पलीमेंट नहीं हो सकती हैं। पावर मिनिस्टर्ज की कान्फ्रेंस हम बुलाने जा रहे हैं। उस में राजाध्यक्ष कमेटी की रिकमेंण्डेशन्ज पर डिस्कशन होगा, उस के बाद हम उन को लागू करेंगे।

जहां तक सेंट्रल सैक्टर की बात है, वह हमने शुरू कर दिया है। जहां तक दिल्ली की बात है—दिल्ली में इन्स्टाल्ड कैपेसिटी 800 मैगावाट है, प्रोडक्शन 500 मैगावाट है और जो इस वक्त डिमाण्ड हैं वह 450 के करीब चलती है। इस में 50–60 मैगावाट पावर सरप्लस रहती है, किसी दिन ज्यादा हो जाती है, किसी दिन कम हो जाती है। जो जैनरल ट्रेण्ड है, वह यह है।

जहां तक नये यूनिट्स का सवाल है, मैंने बतलाया है कि एक नया यूनिट हम दिल्ली में लगाने जा रहे हैं जो 210 मैगावाट का होगा और अगले साल 1981 के आखिर में आजायेगा इस के अलावा कुछ और यूनिट्स भी लगाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। सिंगरौली, वैरासूल और सलाल–ये तीन सेन्ट्रल यूनिट्स लग रहे हैं, जिन से दिल्ली को भी पावर मिलेगी। वैरासूल तो अगले साल से शुरू हो जायगा...

श्री रशीद मसूद: जैनरल मैनेजर का क्या हुआ?

[شری رشید مسعود : جنرل منیجر کا کیا ہوا ؟]

श्री विक्रम महाजन: यहां पर हम कुछ री–स्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं। इसके बारे में जब हम फाइनल डिसीज़न ले लेंगे, तब उस के बारे में फैसला किया जायगा। जहां तक जैनरल मैनेजर की पोस्ट का ताल्लुक है, उस में फिलहाल कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही है, जो प्रेज़ेन्ट इन्कमबेन्ट हैं वह काम कर रहे हैं हमने दिल्ली के एम० पीज० और प्रतिनिधियों को बुलाया है–उन से बात कर के फिर कोई फाइनल डिसीज़न रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में लेंगे।

20.58 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 23, 1980/2 Pausa 1902 (Saka),